सतत विकास की आधारशिला है पारदर्शिता

ग्लोबल फोरम जैसी संस्थाओं के कार्यों के माध्यम से संभव हो पाया : सीतारमण

नयी दिल्ली, 02 दिसंबर. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पारदर्शिता को सतत विकास की आधारशिला बताते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देकर लोगों का सहयोग हासिल किया है और अर्थव्यवस्था को गति दी है. सीतारमण ने यहां ग्लोबल फोरम की 18वीं आम बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के लिए कर मामलों में पारदर्शिता सदैव प्रशासनिक सुधारों से कहीं अधिक रही है.

यह उस गहरे सिद्धांत से जुड़ा है कि आर्थिक शासन की नींव निष्पक्षता और उत्तरदायित्व पर आधारित होनी चाहिये. जब आम लोग और कंपनियां अपना उचित कर अदा करती हैं और कर चोरी को प्रभावी रूप से रोका जाता है, तब समाज अधिक सशक्त और समानतापूर्ण बनता है. उन्होंने कहा, पारदर्शिता को केवल अनुपालन के उपकरण के रूप में नहीं, बल्कि सतत विकास और राजकोषीय सुदृढ़ता की आधारशिला के रूप में देखना आवश्यक है. भारत का अनुभव इस समझ को और मजबूत करता है. मौजूदा सरकार के अनुभवों को साझा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले दशक में सरकार ने स्वैच्छिक अनुपालन में स्पष्ट वृद्धि देखी है.

नागरिक तब अधिक सहयोग देते हैं जब उन्हें विश्वास होता है कि प्रणाली ईमानदारी को प्रोत्साहित करती है और कर चोरी के खिलाफ दृढ़तापूर्वक कार्रवाई करती है. यह प्रवर्तन से नहीं बल्कि स्पष्टता, सरलीकरण और करदाताओं के साथ विश्वास निर्माण के निरंतर प्रयासों से भी संभव हुआ है.

> सीतारमण ने भविष्य की चुनौतियों के बारे में बात करते हुए कहा कि उनसे निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है. अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण, नये वित्तीय उत्पादों का उभरना और लाभकारी स्वामित्व की बदलती संरचनाएं अधिकार क्षेत्रों के बीच निरंतर सहयोग की मांग करती हैं. गोपनीयता और साइबर सुरक्षा को भी अत्यंत सावधानी के साथ बनाये रखना होगा. ये ऐसी चुनौतियां नहीं हैं जिन्हें कोई एक देश अकेले हल कर सके. इनके लिए समन्वय, विश्वास और प्रासंगिक जानकारी का समयबद्ध आदान-प्रदान आवश्यक है. उन्होंने कहा कि एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में जहां परस्पर निर्भरता जीवन का हिस्सा है, वहां अधिकार क्षेत्रों के बीच स्थिर और विश्वसनीय संबंध अनिवार्य हैं. यह फोरम अनेक तरीकों से प्रतिदिन ऐसे संबंधों का निर्माण करता है.

रेपो रेट घटी तो एफडी पर ब्याज घटेगा

नई दिल्ली. आरबीआई की बैठक से पहले विशेषज्ञों की चेतावनी—रेपो रेट घटा तो बैंकों की एफडी दरें भी नीचे आएंगी. भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक दिसंबर में शुरू होने जा रही है और इस बार रेपो रेट में कटौती की संभावना जताई जा रही है. अगर आरबीआई रेपो रेट घटाता है, तो बैंकों द्वारा फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में कटौती लगभग तय मानी जा रही है. विशेषज्ञों के अनुसार, जो निवेशक एफडी में पैसा लगाना चाहते हैं, उन्हें मौजूदा उच्च ब्याज दरों का लाभ उठाने के लिए जल्द कदम उठाना चाहिए. एसबीआई, एचडीएफसी , आईसी आईआईसी, बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक सहित कई बैंकों की वर्तमान एफडी दरें 1 से 5 वर्ष अवधि के लिए 6.25प्रतिशत से 6.60प्रतिशत के बीच हैं.

भारत से आयात बढ़ाने पर काम कर रहा है रूस

नयी दिल्ली, 02 दिसंबर. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से पहले उनके प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मंगलवार को कहा कि भारत के साथ व्यापार असंतुलन के बारे में रूस अवगत है और उनका देश भारत से आयात बढ़ाने पर काम कर रहा है. पेस्कोव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूस की सरकारी समाचार एजेंसी स्पूतनिक द्वारा यहां आयोजित एक वार्ता में यह भी कहा कि पुतिन सरकार डॉलर से इतर व्यापार के विकल्प के समर्थन में है.

उन्होंने रूसी तेल की बिक्री पर अमेरिकी प्रतिबंध को अवैध बताया. उन्होंने कहा कि इस समय दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 63 अरब डॉलर का है जिसे साल 2030 तक बढ़ाकर 100 अरब डॉलर का करने का लक्ष्य है. एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने स्वीकार किया कि दोनों देशों के बीच वास्तव में व्यापार असंतुलन है, और कहा हम इससे अवगत हैं. उन्होंने कहा कि रूस भारत से आयात बढ़ाने के उपायों पर विचार कर रहा है, सिर्फ वस्तु व्यापार नहीं सेवा व्यापार भी. श्री पुतिन की भारत यात्रा से एक दिन पहले बुधवार को आयातकों के एक फोरम का आयोजन किया जायेगा जिसमें इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी. उन्होंने कहा, हम भारत में अपने समकक्षों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि भारत से व्यापार बढ़ाया जा सके. उन्होंने डॉलर से इतर स्थानीय मुद्रा में व्यापार के बारे में कहा कि रूस अपने सहयोगी देशों के साथ व्यापार को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहता है जिससे कोई तीसरा देश व्यापार को प्रभावित न कर सके. उन्होंने कहा, डॉलर के इस्तेमाल के हमारे अधिकार से हमें वंचित किया गया. इसलिए हमने राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार करना शुरू किया. श्री पेस्कोव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की हिस्सेदारी घट रही है.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ओएफएस खुलेगा

नयी दिल्ली, 02 दिसंबर. केंद्र सरकार बैंक ऑफ महाराष्ट्र की पांच प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी जिसके लिए बिक्री प्रस्ताव मंगलवार को खुलेगा.

बैंक ने सोमवार को शेयर बाजार को बताया कि सरकार वित्तीय सेवा विभाग के माध्यम से बैंक की कुल चुकता पूंजी का पांच प्रतिशत यानी 10 रुपये अंकित मूल्य वाले 38,45,77,748 शेयर बेचेगी. इसकी न्यूनतम कीमत 54 रुपये रखी गयी है. इस प्रकार सरकार को 2,076 करोड़ रुपये से अधिक की आमदनी होने की उम्मीद है.

इसके अलावा 7,69,15,549 शेयर (एक प्रतिशत) ग्रीन-शू विकल्प के तहत होंगे जिसकी बिक्री करने पर सरकार बाद में विचार कर सकती है. बैंक ने बताया कि वह 75 हजार इक्विटी शेयर अपने कर्मचारियों को भी दे सकती है. बीएसई में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शेयर 1.54 प्रतिशत की गिरावट के साथ 57.66 रुपये पर बंद हुआ. गैर-खुदरा निवेशकों के लिए ओएफएस 02 दिसंबर को सुबह 9-15 बजे खुलेगा और दोपहर बाद 3-30 बजे बंद होगा.

एचपी ने लेजर एम300 सीरीज में पेश किये तीन नये प्रिंटर

नयी दिल्ली, 02 दिसंबर. कंप्यूटर हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी एचपी इंडिया ने लेजर एम 300 सीरीज का विस्तार करते हुए तीन नये मॉडल भारतीय बाजार में पेश करने की घोषणा की है. कंपनी ने मंगलवार को बताया कि एचपी लेजर 335डीएन, लेजर 335डीडब्ल्यू, और एमएफपी 355एचडीएलडब्ल्यू देश के एसबीएम, एंटरप्राइज और प्रिंट शॉप सेगमेंट के लिए एम300 मोनोक्रोम लेजर पोर्टफोलियो को मजबूत बनाते हैं. ये ऑटो-डुप्लेक्स प्रिंटर हैं जो हाई-वॉल्यूम और हाई-परफॉर्मेंस प्रिंटिंग के लिए डिजाइन की गयी इस नयी रेंज में तेज आउटपुट, कम ऑपरेटिंग लागत और बेहतर दक्षता देते हैं.

सोना सस्ता हुआ, चांदी फिर महंगी

22-24 कैरेट सोने में आई गिरावट

सर्राफा बाजार में आज सोने का बड़ा बदलाव

नई दिल्ली, 02 दिसंबर. सर्राफा बाजार में 2 दिसंबर 2025 को सोने के दाम में गिरावट और चांदी के भाव में तेजी देखी गई. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोना आज 659 रुपये सस्ता हुआ, जबकि चांदी 243 रुपये महंगी होकर 1.75 लाख रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गई.

22 कैरेट सोने की कीमत भी घटकर 117377 पर आ गई है. भारतीय सर्राफा बाजार में मंगलवार, 2 दिसंबर 2025 को सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली, जबकि चांदी के भाव में तेजी आई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोना सोमवार शाम के मुकाबले 659 रुपये सस्ता होकर 128141 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. इसी तरह 22 कैरेट सोना 604 रुपये गिरकर ?117377 पर ट्रेड हुआ. दूसरी ओर, चांदी 243 रुपये महंगी हुई और इसका भाव 175423 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया.

> भारत के सर्राफा बाजार में आज यानी मंगलवार, 2 दिसंबर 2025 को सोने और चांदी की कीमतों में अलग-अलग रुझान देखने को मिला. जहां सोना लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ खुला, वहीं चांदी की कीमतों में तेजी बनी रही. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी ताज़ा दरों के मुताबिक 24 कैरेट सोना सोमवार शाम की तुलना में 659 रुपये सस्ता होकर 128141 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया.

एप्पल ने अमर सुब्रमण्या को दी बड़ी जिम्मेदारी

सिरि को स्मार्ट बनाने के लिए नई लीडरशिप

एप्पल इंटेलिजेंस सुधारने की बड़ी तैयारी

नई दिल्ली, 02 दिसंबर. एआई रेस में पिछड़ती दिख रही एप्पल ने बड़ा दांव खेलते हुए भारतीय मूल के अमर सुब्रमण्या को एआई टीम का वाइस-प्रेसिडेंट बनाया है. गूगल जेमिनी और माइक्रोसॉफ्ट के एआई प्रोजेक्ट्स में अहम भूमिका निभा चुके अमर अब सिरि के मेगा अपग्रेड और एप्पल इंटेलिजेंस के ओवरहॉल को लीड करेंगे. उनकी एंट्री को एपल की एआई रणनीति का टर्निंग प्वाइंट माना जा रहा है.

एप्पल ने आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की तेज होती रेस में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए भारतीय मूल के अमर सुब्रमण्या को एआई टीम का नया वाइस-प्रेसिडेंट नियुक्त किया है. गूगल में जेमिनी असिस्टेंट और डीपमाइंड के साथ कई हाई-इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स को लीड करने के बाद, अमर कुछ ही महीने माइक्रोसॉफ्ट में रहकर एपल से जुड़ गए. वे अब मशीन लर्निंग रिसर्च, फाउंडेशन मॉडल्स और सिरि के बड़े अपग्रेड को दिशा देंगे.

एप्पल के सामने इस समय दो बड़े एआई चैलेंज

एप्पल इंटेलिजेंस में आ रही गलतियों को ठीक करना, और दूसरा, सिरि के डिले हो रहे मेगा अपग्रेड को समय पर पूरा करना. नोटिफिकेशन समरी में फेक हेडलाइंस, गलत कंटेंट जेनरेशन और फेल टेस्टिंग ने कंपनी की चिंता बढ़ा दी थी. इसके अलावा सिरि को ऐप-कंट्रोल और कॉन्टेक्सचुअल अवेयरनेस जैसी क्षमताएं देने की योजना अब 2026 के मध्य तक लटक चुकी है. माना जा रहा है कि अमर की एंट्री से ये दोनों प्रोजेक्ट नए सिरे से गति पकड़ेंगे. वे एपल के इन-हाउस विकसित हो रहे 1-ट्रिलियन पैरामीटर मॉडल और गूगल जेमिनी के साथ होने वाली बड़ी लाइसेंसिंग डील को इंटीग्रेट करेंगे. उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि अमर सुब्रमण्या एपल को एआई रेस में वह तेजी दिला सकते हैं जिसकी कंपनी को लंबे समय से जरूरत थी.

जियो और एनएचएआई में व्यापारिक करार

एसएमएस, हाई-प्रायोरिटी कॉल के जरिए यात्रियों तक पहुंचेगा अलर्ट

नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और यात्रा अनुभव को अधिक सुगम बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रिलायंस जियो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं.

इस साझेदारी के तहत 50 करोड़ से अधिक जियो ग्राहकों के लिए पूरे नेशनल हाईवे नेटवर्क पर एक टेलीकॉम आधारित सेफ्टी अलर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा. जियो के 4-5प्रतिशत नेटवर्क के जरिए वाहन चालकों को दुर्घटना संभावित क्षेत्रों, कोहरे वाले हिस्सों, आवारा पशु जोन और इमरजेंसी डायवर्जन की पहले से जानकारी मोबाइल पर मिलेगी. सुरक्षा संदेश यात्रियों तक एसएमएस, व्हाट्सएप और हाई-प्रायोरिटी कॉल के माध्यम से पहुंचेंगे. यह पूरी तरह ऑटोमेटेड सिस्टम जियो मोबाइल यूजर्स के लिए नेशनल हाईवे पर या उसके आसपास काम करेगा और किसी भी अतिरिक्त सड़क-किनारे हार्डवेयर की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यह मौजूदा टेलीकॉम टावरों के जरिए संचालित होगा. चेयरमैन संतोष कुमार यादव ने कहा कि यह पहल यात्रियों को समय पर सटीक जानकारी उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम कदम है, जिससे वे पहले से ही सतर्क होकर सुरक्षित ड्राइविंग अपना सकेंगे. उन्होंने भरोसा जताया कि यह पहल तकनीक आधारित रोड सेफ्टी मैनेजमेंट में एक नया मानक स्थापित करेगी. वहीं रिलायंस जियो के प्रेसिडेंट ज्योतिंद्र ठक्कर ने कहा कि यह पहल जियो के विस्तृत टेलीकॉम नेटवर्क की ताकत का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर सुरक्षा अलर्ट पहुंचाने में सक्षम होगी और इससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा और अधिक सुरक्षित बनेगी.

चालू खाते का घाटा कम होकर 12.3 अरब डॉलर

मुंबई, 02 दिसंबर. चालू खाते का घाटा मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में कम होकर 12.3 अरब डॉलर रह गया जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.3 प्रतिशत है. पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सीएडी 20.8 अरब डॉलर (जीडीपी का 2.2 प्रतिशत) रहा था. रिजर्व बैंक द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों में बताया गया है कि वस्तु व्यापार घाटा 87.4 अरब डॉलर रहा. यह एक साल पहले 88.5 अरब डॉलर था. वहीं, सेवाओं के निर्यात से प्राप्त शुद्ध आय 44.5 अरब डॉलर से बढ़कर 50.9 अरब डॉलर पर पहुंच गयी.

हरमनप्रीत कौर बनीं बैंक की नयी ब्रांड एंबेसडर

नयी दिल्ली, 02 दिसंबर. भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और विश्व कप विजेता हरमनप्रीत कौर पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एंबेसडर बनी हैं.

पीएनबी के कॉर्पोरेट कार्यालय में बैंकिंग ऑन चैंपियंस की व्यापक थीम के तहत आयोजित एक समारोह में ब्रांड एंबेसडर के रूप में उन्हें अनुबंधित किया गया. इस मौके पर अपनी नयी जिम्मेदारी की शुरुआत पर हरमनप्रीत ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू, पीएनबी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक चंद्र के साथ मिलकर बैंक के चार वित्तीय उत्पादों का अनावरण किया.

समाचार विशेष

राजस्थान में बड़ा राजनीतिक बदलाव तय?

जयपुर. राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. राज्य में हाल ही में हुई व्यापक नौकरशाही फेरबदल के बाद अब मंत्रिमंडल पुनर्गठन और विस्तार की चर्चा तेज हो गई है. अंता विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद राजनीतिक हलकों में यह माना जा रहा है कि सरकार आगामी चुनावी चुनौतियों से पहले अपनी टीम में व्यापक बदलाव कर सकती है.

सरकार के वर्तमान मंत्रिमंडल में 24 मंत्री हैं, जबकि संविधान के मुताबिक अधिकतम 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं. छह पदों के रिक्त होने से नए चेहरों के लिए रास्ता खुला हुआ है.

भाजपा के भीतर गुटीय राजनीति और भौगोलिक प्रतिनिधित्व दोनों इस फेरबदल के महत्वपूर्ण पहलू माने जा रहे हैं. शेखावाटी, मेवाड़, पूर्वी राजस्थान, आदिवासी क्षेत्र

इन इलाकों से नए नामों को शामिल करने पर मंथन चल रहा है. पार्टी के भीतर गुर्जर और मेघवाल समुदायों को भी मंत्रिमंडल में अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग उठ रही है. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रभाव वाले गुट को संतुलित करना भी पार्टी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है. राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि आगामी फेरबदल में राजे समर्थक नेताओं को भी सम्मानजनक प्रतिनिधित्व देने पर विचार चल रहा है, ताकि संगठन के भीतर किसी भी प्रकार की असंतोष की स्थिति न बने.

नॉन-परफॉर्मिंग मंत्रियों की कुर्सी खतरे में

सूत्रों के अनुसार, मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ खाली पदों की पूर्ति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कुछ नॉन-परफॉर्मिंग मंत्रियों को बाहर किए जाने की भी संभावना है. कई विभागों में बदलाव की भी चर्चा है. मुख्यमंत्री ने हाल के दिनों में कई वरिष्ठ नेताओं से फीडबैक लिया है, जिसे मंत्रियों के प्रदर्शन की समीक्षा की प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है. नौकरशाही में हालिया बड़े बदलावों के बाद माना जा रहा है कि सरकार अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरे होने से पहले मंत्रिमंडल को भी नया रूप दे सकती है. लगातार बैठकों, संगठन से मिल रहे संकेत और नेताओं की गतिविधियों से यह स्पष्ट है कि राजस्थान की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है.

महाराष्ट्र में बनेगा नया महागठबंधन!

शशिकांत शिंदे का बड़ा दावा, बोले- शरद और शिंदे गुट आएंगे साथ

मुंबई. महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर गठबंधन के मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है. कुर्डुवाडी नगरपालिका चुनाव के प्रचार के दौरान एनसीपी (शरद गुट) के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कुर्डुवाडी में शिवसेना शिंदे गुट के साथ किया गया स्थानीय गठबंधन भविष्य का संकेत है.

आने वाले समय में पूरे महाराष्ट्र में भी शरद गुट और शिंदे गुट के बीच बड़ा गठबंधन हो सकता है. शशिकांत शिंदे ने बिना नाम लिए भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे को भाजपा इस्तेमाल कर रही है. यह गठबंधन (कुर्डुवाडी में) सिर्फ शुरुआत है. आगे चलकर महाराष्ट्र की जनता देखेगी कि असली शिवसेना और असली एनसीपी किसके साथ खड़ी है.

सीटों को लेकर तनाव चरम पर

सोलापुर जिले में भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच नगरपालिका सीटों को लेकर तनाव पहले से चरम पर है. ऐसे में शरद गुट का शिंदे गुट के साथ खुलकर आना महायुति गठबंधन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि 2022 में शिवसेना और एनसीपी के विभाजन के बाद पहली बार दोनों मूल पार्टियों (उद्धव ठाकरे को छोड़कर) के बीच फिर से नजदीकियां बढ़ रही हैं. अगर यह गठबंधन राज्य स्तर पर हुआ तो महायुति (भाजपा-शिंदे गुट-अजीत गुट) में भारी उथल-पुथल हो सकती है. कुर्डुवाडी नगरपालिका चुनाव अब सिर्फ स्थानीय चुनाव नहीं रह गया है - यह महाराष्ट्र की अगली बड़ी राजनीतिक उलटफेर की पहली सीढ़ी बनता दिख रहा है.

विशेष | कांग्रेस के सामने बड़ा सवाल- लड़े किससे और बचे कैसे?

बिहार के बाद बंगाल पर भाजपा की नजर

नई दिल्ली. बिहार चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि अब भाजपा की अगली बड़ी लड़ाई बंगाल में होगी. उन्होंने कहा कि जिस तरह गंगा बिहार से होकर बंगाल जाती है, उसी तरह बिहार की जीत भाजपा को बंगाल तक ले जाएगी.

इस बयान के बाद तस्वीर साफ है बंगाल 2026 भाजपा का अगला बड़ा लक्ष्य है. उधर, कांग्रेस की हालत बिहार में भी बहुत कमजोर रही और वह सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई. इससे उसका राजनीतिक वजन और कमजोर दिखा.

कांग्रेस के लिए मुश्किल

कांग्रेस के सामने बंगाल में एक बड़ी उलझन है. किससे लड़ें? ममता बनर्जी से, जो राज्य में पूरी तरह हावी हैं या भाजपा से जो तेजी से मजबूत हुई है और कांग्रेस को पूरी तरह किनारे कर रही है. कांग्रेस का बंगाल में लगातार गिरना साफ दिखता है. 2011 में वह ञस्ष्ट की सहयोगी थी और 42 सीटें जीती थीं. 2016 में लेफ्ट के साथ चुनाव लड़कर 44 सीटें मिलीं, लेकिन जमीन कमजोर होने लगी. 2021 तक हालत इतनी खराब हो गई कि कांग्रेस 92 सीटों पर लड़कर भी एक भी सीट नहीं जीत सकी और उसका वोट शेयर सिर्फ 3 प्रतिशत रह गया.

भाजपा का उभार- भाजपा की बंगाल में बढ़त पिछले दशक की सबसे तेज राजनीतिक बढ़तों में से एक है. 2016 में उसके पास सिर्फ 3 सीटें थीं. 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 18 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया. 2021 विधानसभा में वह सीधे मुख्य विपक्षी बन गई77 सीटें और 38 प्रतिशत वोट शेयर के साथ. अगर यह रफ्तार जारी रही, तो कांग्रेस पूरी तरह मुकाबले से बाहर हो सकती है.

टीएमसी अकेले लड़ेगी और अकेले जीतेगी- कांग्रेस की परेशानी यह भी है कि ममता बनर्जी उसे कोई खास जगह नहीं देना चाहतीं. 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही उन्होंने कहा था कि टीएमसी बंगाल की सभी 42 सीटें अकेले लड़ेगी और कि इंडिया गठबंधन दिल्ली के लिए है, बंगाल के लिए नहीं.

क्या भाजपा आगे बढ़ाएगी नीतीश की विरासत?

पटना. बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के साथ ही यह भी अहम है कि इस बार भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी है. दूसरे नंबर पर जदयू है. जिस तरह मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हुआ, उससे इस पर चर्चा होने लगी है कि क्या बिहार में सत्ता के समीकरण बदलेंगे और क्या भाजपा ही नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ाएगी.

पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गृह विभाग नहीं है. भाजपा ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह विभाग दिया है. इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं. चुनाव के दौरान जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. उन पर हत्या और गैंगरेप जैसे अपराधों में शामिल होने का आरोप लगाया गया, लेकिन भाजपा ने इन आरोपों की परवाह नहीं की. सम्राट चौधरी को टिकट ही नहीं दिया गया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके पक्ष में रैली भी की. प्रचंड जीत के बाद सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम पद के साथ-साथ गृह विभाग भी दे दिया गया.

इससे ये तो साफ है कि भाजपा बिहार में स्थानीय नेतृत्व की नई खेप तैयार कर रही है. पहले बिहार भाजपा के नेता के तौर पर सुशील मोदी का नाम ही सबकी जुबान पर आता था. अब भाजपा बिहार में सम्राट चौधरी को अपने बड़े नेता के तौर पर प्रॉजेक्ट कर रही है. कानून-व्यवस्था यहां चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा था. गृह विभाग जितना अहम है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी.

विशेष फोर्स का गठन

पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जिस तरह सम्राट चौधरी ने अपराधियों को चेतावनी दी कि उनके लिए बिहार में कोई जगह नहीं है, उसमें कहीं न कहीं यूपी के योगी है. यूपी की तर्ज पर ही चौधरी ने रोमियो से निपटने के लिए विशेष फोर्स बनाने का ऐलान किया है. यूपी में योगी ने एंटी रोमियो स्क्वैड बनाई थी. यूपी में जहां बुलडोजर और एनकाउंटर मॉडल की चर्चा रही है, वहीं सम्राट चौधरी ने 400 माफियाओं की लिस्ट बनाई है और कहा है कि इन पर सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी. हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसा कोर्ट की इजाजत लेकर ही किया जाएगा.